ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेज: 4 संस्कार देने और भाई बहन के प्रेम का पर्व है कर्मा

रविवारीय 08-14 सितंबर 2019, संस्करण-1, अंक -5 | हिन्दी साप्ताहिक | R.N.I. No. JHAHIN 00962 | कुल पृष्ठ 4 | मूल्य 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट परिवार की ओर से आप सभी पाठकों को करमा पूजा की हार्दिक शुभकानाये

सूचना

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।
greenrevolt2019@gmail.com
9798166006

ट्रैफिक नियमों में सख्ती और भारी जुर्माने के भय से रांची की सड़कों पर वाहनों की संख्या घटी, पर्यावरण को होगा इसका लाभ

रांची में ध्वनि और वायू प्रदूषण में कमी

रांची : नये ट्रैफिक नियमों से जनता क्षुब्ध और परेशान है, आये दिन पुलिस के साथ बहस और लड़ाई हो रही है। और जुर्माने के भय ये लोग अपने वाहनों को लेकर सड़क पर निकलने से परहेज कर रहे हैं। वहीं इस कानून का एक दूसरा पहलू भी है जो पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। महज एक सप्ताह में ही रांचीवासियों का मानना है कि, सड़कों पर अवैध वाहनों के न चलने से ट्रैफिक सामान्य तो है हीं साथ ही शोर गुल भी कुछ हद तक कम हुये हैं। इसका एक दूरगामी असर ये भी हो सकता है कि रांची की आबोहवा में प्रदूषण का असर घटेगा। दो प्रकार के वाहन सड़कों पर बंद हैं। एक जिनके कागजात दुरूस्त नहीं हैं, दूसरे वह व्यावसायिक वाहन जिनका परमिट नहीं था और अब तक अवैध तरीके से चला रहे थे ।

बिना परमिट के वाहन हैं नदारद

रांची में प्रदूषण के मुख्य कारक डीजल ऑटो हैं जिनकी निबंधित संख्या लगभग 2335 है। लेकिन लगभग 8000 से ज्यादा गैरनिबंधित डीजल ऑटो का परिचालन हो रहा था। एकाएक कानून के भय से इनका परिचालन बंद है और इस कारण से वायू प्रदूषण ही नही ध्वनि प्रदूषण भी घटा है।शहर के सबसे व्यस्ततम और घनी आबादी वाले मार्ग रातू रोड में भी ट्रैफिक जाम में कमी आयी है। वहीं महात्मा गांधी मार्ग से गुजरने वालों को भी कहना है कि अब जाम की स्थिति में अब कमी आई है। हालांकि ई रिक्शा के बंद होने से आम जन को असुविधा भी हुयी है।

प्रदूषण प्रमाणपत्र बनाने वालों की चांदी

अब तक जिन प्रदूषण प्रमाणपत्र बनाने वालों का व्यवसाय ठंढा पड़ा हुआ था एकाएक उनकी चांदी हो गयी है। रांची के ऐसे सभी काउंटरों पर सुबह से लेकर रात तक लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। इस भीड़ को देख कर इन प्रदूषण प्रमाणपत्र बनाने वालों ने 50 की जगह 60 , 80 के जगह पर 100 और 120 की जगह पर 200 रूपये वसूलने शुरू कर दिये हैं। इस पूरे वाकये में सबसे अहम बात ये है कि वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र तो बन जा रहा है, पर वाहनों की सही तरीके से जांच न केबराबर होती है। तकरीबन सभी वाहन प्रदूषण जांच में पास हो जाते हैं।

प्रदूषण और बेतहाशा बने अपार्टमेंट ने खत्म कर दी रांची में नोर्वेस्टर की बारिश

रांची के पुराने बाशिंदों का कहना है कि पहले प्रतिदिन सेकेंड हाफ में बारिश जरूर होती थी और थोड़े से तापमान के बढने पर ही नोर्वेस्टरके बादल बनते थे जिससे यहां बारिश होती थी। पहले यदा कदा बर्फबारी भी हुआ करती थी। इन्हीं कारणों से रांची को संयुक्त बिहार के काल में ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया था। राज्य बनने के बाद यहां चारो ओर बड़े बड़े अपार्टमेंटों का निर्माण हुआ और आस पास की हरियाली खत्म कर दी गयी। इस कारण से गर्मी के बढने पर भी नोर्वेस्टर के बादलों का निर्माण रूक गया और राहत की बारिश भी बंद हो गयी। वर्तमान में रांची के ग्रीनलैंड के अलावा बहुत सारे नदियों और जलाशयों के कैचमेंट में भी निर्माण कर दिये गये हैं।

दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में अधिकतर भारत में

कुछ महिने पहले एक एजेंसी ने जांच कर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की जो सूची सौंपी थी उसमें से ज्यादतर शहर भारत के थे। दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। 80 के दशक में दिल्ली के आकाश से गुजरने पर हवाई यात्रियों को दिल्ली काफी हरी भरी नजर आती थी और तब इसे गार्डेन सिटी कहा जाता था। अब दिल्ली का आकाश धुंध से भरा रहता है। दिल्ली में धुंध और प्रदूषण के कारण भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट मैच को कम विजिबिलिटी के कारण रद्द करना पड़ गया था। इन सब के बीच दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को वन वे करने पर दो दिनों में ही प्रदूषण स्तर घट गया था। लेकिन लोगों के विरोध के कारण यह नियम फेल हो गया।

स्कूलों को स्वच्छता के लिये 4.45करोड़ देगी सरकार

रांची : विद्यालयों में स्वच्छता पर पुरस्कार के लिये सरकार 4.45 करोड़ देगी। यूनिसेफ ने भी स्वच्छता पुरस्कार के लिये 54.5 लाख रूपये देने का एलान किया है। इसके तहत 119 विद्यालयों को पुरस्कृत किया जायेगा।

इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनो प्रकार के विद्यालय शामिल हैं। मुख्यमंत्री स्वच्छता पुरस्कार में राज्य के 50 प्लस टू उच्च विद्यालय भी शामिल किये जायेंगे। इसमें पानी, शौचालय, साबून, हाथ धोने के लिये साधन , भवन के मेंटेनेंस के लिये अंक निर्धारित किये गये हैं। और उसके अनुसार ही स्टार ग्रेड दिये जायेंगे।

समूचे झारखंड में प्रकृति पर्व करमा मनाया जा रहा है। करमा हमें प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है।

कपड़े का झोला बांटेगा रांची नगर निगम

रांची : प्लास्टिक के थैलों से शहर को मुक्त करने के उद्देश्य से रांची नगर निगम लोगों के बीच कपड़े का झोला बांटेगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिये निर्देश जारी किये हैं। 11 से 27 सितंबर तक लोगों में कपड़े का झोला वितरण करने के साथ हीं उन्हें प्लास्टिक कैरी बैग के नुकसान के बारे में बताया जायेगा, 2 अक्टूबर को श्रमदान करके प्लास्टिक के कचड़े को रिसाइकल किया जायेगा। इसके बाद प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करने वालों पर सख्ती बरती जायेगी।

तकरीबन पांच दशक पुराने स्वांग वाशरी का जीवन काल हो चुका था समाप्त

सीसीएल प्रबंधन के सूझ-बूझ से बची जान

सावधानी

सीसीएल प्रबंधन ने समय पर कार्रवाई एवं वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण के कारण 50-60 कर्मियों का हादसा होने से बचाया।

रांची :स्वांग वाशरी का निर्माण वर्ष 1970 में हुआ था और स्वांग वाशरी का जीवन काल (49 वर्ष) समाप्त हो चुका था। सीसीएल प्रबंधन ने इस संदर्भ में समय-समय पर उपरोक्त वाशरी का निरीक्षण करता रहा है और स्थिति को देखते हुए सीएमपीडीआई को निरीक्षण हेतु 17 नवम्बर, 2018 को निर्देश दिया। सीएमपीडीआई ने अपना रिपोर्ट सीसीएल प्रबंधन को सौंपा जिसमें कहा गया कि वाशरी मेन बिल्डींग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सीएमपीडीआई के अनुशंसा के आधार पर सीसीएल प्रबंधन ने 18 जुलाई, 2019 को मेन बिल्डींग को बंद कर दिया। सीसीएल प्रबंधन ने स्वांग वाशरी के मेन बिल्डींग को कमजोर एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्र घोषित किया था। प्रबंधन ने अपने कर्मियों को सलाह दिया था कि उस क्षेत्र में नहीं जाये और स्टेकहोल्डर्स को भी वहां जाने से रोकें। 5 सितं. को दोपहर में सीसीएल के कथारा क्षेत्र में स्थित स्वांग वाशरी के मेन बिल्डींग का कुछ हिस्सा अपने-आप गिर गया और किसी भी कर्मी को गंभीर चोट नहीं लगी है।

भूमिगत खान सुरक्षा में सीसीएल अव्वल

भुरकुंडा भूमिगत खान सुरक्षा में प्रथम, चूरी सेकेंड

अरगड्डा में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह पुरस्कार में सीसीएल के सीएमडी ने कहा कि सुरक्षा के इंतजामों के अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। उनका कहना था कि, अधिकारी सुरक्षा इंतजामों पर नियमित मीटिंग करके दुर्घटनाओं की आशंका को खत्म करें।सीसीएल के सेफ्टी बोर्ड की बैठक के अब अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं और दुर्घटनाओं की संख्या कम हुयी है।

खुले खदान माइंस में सुरक्षा के स्तर में अशोका को प्रथम स्थान मिला, टाटा एबी को दूसरा और उरीमारी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। खुली खदान के ग्रुप बी स्तर में रेलीगढा माइंस को पहला करमा माइंस को दूसरा और गिरिडीह को तीसरा स्थान दिया गया।

गांधीनगर अस्पताल में हृदय रोग की निःशुल्क चिकित्सीय शिविर

मैक्स सुपर स्पेशियलिटी, अस्पताल, नई दिल्ली के प्रख्यात डॉ. राजीव राठी करेंगे मरीजों की जांच

रांची :सी.सी.एल. गोपाल सिंह की पहल पर कायाकल्प मॉडल के अंतर्गत केंद्रीय अस्पताल, सीसीएल गांधीनगर, कांके रोड, में 4 सितम्बर, 2019 को दोपहर 12 बजे से निःशुल्कहृदय रोग की जाँच एवं चिकित्सीय सलाह की व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली के प्रख्यात डॉ. राजीव राठी (कार्डियोलॉजिस्ट) 14 सितम्बर, 2019 को केंद्रीय अस्पताल, गांधीनगर आयेंगे, जहां वे मरीजों की निःशुल्क जाँच करेंगे तथा चिकित्सीय सलाह देंगे। इस निःशुल्क हृदय संबंधित चिकित्सीय शिविर का लाभ सभी झारखंडवासी उठा सकते हैं। मरीज के पास यदि पुराने ईलाज की रिर्पोट/जाँच के पेपर है तो उसे अवश्य अपने साथ लाये।

हाइकोर्ट ने वाटर हार्वेस्टिंग में पेश की मिसाल

- 60 लाख लीटर वर्षाजल संचयन हो रहा है झारखंड हाइकोर्ट में।
- हाइकोर्ट परिसर में पांच रिचार्ज पिट बनाये गये हैं।
- 54000 वर्ग फीट से एकत्रित होता है वर्षा जल

रांची : झारखंड हाइकोर्ट भूमिगत जल स्तर को बनाये रखने का आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिवर्ष लाखों लीटर वर्षा जल बचाने में हाइकोर्ट सहयोग कर रहा है। बारिश का पानी बरबाद नहीं हो, उसे एकत्र कर भूगर्भ जल को रिचार्ज किया जा रहा है। कुछ समय पहले हाइकोर्ट परिसर स्थित भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया गया था। परिसर में चार ब्लॉक में हाइकोर्ट बिल्डिंग बना हुआ है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा किया गया है. हाइकोर्ट की छत में औसतन 60 लाख लीटर वर्षा जल एकत्रित होता है। छत पर एकत्रित होनेवाले जल को पाइप के माध्यम से पांच जगहों पर बने रिचार्ज पिट पीट तक लाया गया है।रिचार्ज पिट की चौड़ाई 10 फीट व गहराई 14 फीट है। उसमें बोरिंग किया गया है, जो लगभग 75 फीट गहरा है। इससे छत पर एकत्रित होनेवाला वर्षा जल भूगर्भ में चला जाता है। झारखंड हाइकोर्ट के रेन वाटर हार्वेस्टिंग से प्रतिवर्ष लाखों लीटर वर्षा जल को भूगर्भ में भेजा जा रहा है। यह सिस्टम हाइकोर्ट परिसर में पूरी तरह से सफल हो रहा है।

12 सितंबर को किसान मानधन योजना का झारखंड से शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 12 सितंबर को रांची में एक लाख से अधिक किसानों को संबोधित करेंगे। इसी दिन किसानों को पेंशन देने वाली स्कीम किसान मान धन योजना का शुभारंभ पूरे देश में करेंगे। प्रधानमंत्री सात किसानों को पेंशन स्कीम का प्रमाणपत्र भी देंगे। इस योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री झारखंड से शुरू करने जा रहे हैं।

एक नेशनल पार्क एवं 10 वाइल्ड सेंचुरी इको सेंसेटिव जोन घोषित

रांची: झारखंड हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये एक्टिंग चीफ जस्टिस हरीश चंद्र मिश्र एवं जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राज्य के एक नेशनल पार्क एवं दस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसेटिव जोन घोषित कर दिया। खंउपीठ ने राज्य सरकार को इको सेंसेटिव जोन करने संबंधी नोटिफिकेशन को शपथ पत्र के माध्यम से रिकार्ड पर लाने का निर्देश दिया। सरकार की ओर से अधिवक्ता विकास ने बताया कि बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पारसनाथ वाइल्ड लाईफ सेंचुरी सहित 11 सेंचुरियों को इको सेंसेटिव जोन घोषित किया गया है।

ज्ञात हो कि प्रार्थी महेश राय ने जनहित याचिका दायर कर 11 सेंचुरियों को इको सेंसेटिव जोन घोषित करने की मांग की थी। अब इस फैसले के बाद राज्य में इको सेंसेटिव जोन घोषित करने के लिये कोई कोई सेंचुरी नही है।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में राई - सरसों पर 26 वां वार्षिक राष्ट्रीय समूह बैठक का आयोजन

धान की परती भूमि में राई सरसों खेती की काफी संभावना : डॉ .कुरील

देश में पेट्रोलियम और सोना के बाद देश में सर्वाधिक आयात खाद्य तेलों का ही होता है : डॉ. आरएस कुरील

राज्य के करीब 3.05 लाख हेक्टेयर में राई - सरसों की खेती की जाती है।

रांची :भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के सौजन्य से पूरे देश में संचालित अखिल भारतीय समन्वित राई - सरसों अनुसंधान परियोजना के अनुसंधान उपलब्धियों एवं भावी रणनीति तय करने के लिए कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 26 वीं वार्षिक राष्ट्रीय समूह बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एवं उद्घाटन करते हुए बीएयू कुलपति डॉ आरएस कुरील ने बताया कि देश में पेट्रोल एवं सोना के बाद खाद्य तेल का सर्वाधिक आयात किया जाता है। गत वर्ष देश ने करीब 75 हजार करोड़ रूपये का खाद्य तेल आयात किया. जबकि दशकों से देश में राई - सरसों का उत्पादन एवं उत्पादकता स्थिर है और क्षेत्र एवं उत्पादन के विस्तार में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है. इस परिप्रेक्ष्य में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा राई - सरसों पर बेहतर अनुसंधान, उन्नत किस्मों का विकास एवं बेहतर रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।

कुलपति डॉ कुरील ने बताया कि कुछ वर्षो से झारखण्ड राज्य में इसकी खेती का क्षेत्रफल बढा है। वर्ष 2017-18 में राज्य के करीब 3.05 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हुई और कुल उत्पादन 2.18 लाख टन दर्ज किया गया. राज्य के धान खेत की परती पड़ी भूमि में राई - सरसों फसल क्षेत्र विस्तार की व्यापक संभावना है। कुलपति ने बताया कि झारखण्ड राज्य में मौसम की विषम स्थिति तथा प्रत्येक वर्ष धान की खेती के उपरांत परती पड़ी करीब 14.6 लाख हेक्टेयर भूमि में राई - सरसों की खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है.राज्य की खेती योग्य करीब 38 लाख हेक्टेयर भूमि में से करीब 28 लाख हेक्टेयर भूमि में ही खेती की जाती है. राज्य के करीब 3.05 लाख हेक्टेयर में राई - सरसों की खेती की जाती है. राज्य के किसानों के हित में तथा उनकी आमदनी में वृद्धि के लिए राज्य के अतिरिक्त 3.0 लाख हेक्टेयर भूमि में रबी मौसम में इसकी खेती को बढ़ावा देकर चालु खरीफ मौसम में हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है.

डॉ कुरील ने बताया कि बीएयू द्वारा स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुकूल बिरसा राई, बिरसा तोरी व बिरसा टीएम - 129 किस्मों के विकास के लिए शोध जाँच प्रगति पर है. विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सरसों किस्म शिवानी का प्रदर्शन राज्य में काफी संतोषजनक पाया गया है. राज्य के किसान कम अवधि वाली (105-110 दिनों) शिवानी किस्म के आलावा पूसा सरसों - 25, पूसा अग्रणी एवं पूसा महक किस्मों से सिंचित एवं असिंचित अवस्था में बढ़िया पैदावार ले सकते है. इसकी खेती को बढ़ावा देकर देश में खाद्य तेल की कमी को दूर किया जा सकता है. जिससे राष्ट्रीय जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी. इस अवसर पर कुलपति ने राई - सरसों अनुसंधान परियोजना का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, बीज प्रौद्योगिकी एवं झारखण्ड में राई - सरसों की उन्नत खेती नामक पुस्तक का विमोचन भी किया।बतौर मुख्य अतिथि डॉ एसएस बग्गा, नेशनल प्रोफेसर (आईसीएआर), पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,लुधियाना ने बताया कि हरियाणा में राई - सरसों का उत्पादन करीब 2 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि देश के प्रधान उत्पादक राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में औसत उत्पादन राष्ट्रीय औसत 14 क्विंटल से ज्यादा है. झारखण्ड एवं बिहार राज्य में इन फसलों का उत्पादन काफी कम है. इस फसल की उन्नत किस्मों के विकास तथा इसके पैकेज प्रणाली को विज्ञान आधारित बनाने की जरूरत है. अखिल भारतीय समन्वित राई - सरसों अनुसंधान परियोजना के राष्ट्रीय निदेशक डॉ पीके राय ने राई - सरसों फसल पर राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे शोध कार्यो का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. आईसीआर - राई - सरसों अनुसंधान निदेशालय की वार्षिक रपट के अनुसार झारखण्ड राज्य में इस फसल की खेती के परिणाम काफी उत्साहजनक रहे है .रपट के अनुसार राज्य में बारानी अवस्था में राई - सरसों की अधिकतम 47.7 प्रतिशत तक उपज में बढ़ोतरी प्राप्त हुई है और अधिकतम अतिरिक्त औसत शुद्ध लाभ 9,687 रूपये प्रति हेक्टेयर पाया गया है. शोध में असिंचित अवस्था में राज्य के किसानों की स्थानीय किस्मों की तुलना में शिवानी किस्म से सर्वाधिक 55.9 प्रतिशत तक उपज में बढ़ोतरी के साथ औसत पैदावार 1,034 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज किया गया है. वैज्ञानिकों ने उन्नतशील किस्मों एवं बेहतर शस्य विधियों को अपनाकर झारखण्ड राज्य में राई - सरसों का उत्पादन एवं उत्पादकता काफी हद तक बढ़ाये जाने की संभावना जताई है। डॉ राय ने बताया कि वर्ष 2018-19 में पूरे देश में इस फसल के लिए मौसम काफी अनुकूल रहने के कारण केन्द्रों में औसतन 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हुआ. अखिल भारतीय समन्वित राई - सरसों शोध परियोजना के तहत देश के 11 राज्यों के 14 विभिन्न केन्द्रों में कृषि पारिस्थितिकी के अनुरूप उन्नत किस्मों के विकास हेतु कार्यक्रम चलाया गया. 46 केन्द्रों में 158 किस्मों का मूल्यांकन तथा 35 समन्वित

शेष पेज 3 पर .....

संयम और सहयोग की जरूरत

देश भर में ट्रैफिक नियम कानूनों में सख्ती और जुर्माने में भारी वृद्धी से बहुत सारे लोग आहत हैं। किसी को यह अत्याचार लग रहा है, किसी को अव्यवहारिक, कुछ इसका उपहास उड़ा रहे हैं और कुछ सरकार का खजाना भरने का तरीका तक कह रहे हैं। इन सभी आरोपों के बरअक्स हम देखें तो यह तथ्य भी सामने आता है कि, आम भारतीय ट्रैफिक नियमों का पालन करने में कोताही बरतता है, वह इसके उल्लंघन का आदी है और नियमों को मानना अपनी तौहीन समझता है। हमारी सोच भी कुछ ऐसी है कि जो ट्रैफिक नियमों को धता बता कर चल देता है उसे ही रसूखदार माना जाता है।

अब वाहनों में प्रदूषण का सर्टिफिकेट रखना भी आवश्यक है, इसके न होने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। इस कारण से पहले जहां वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने में भी लोग कोताही बरतते थे वहां अब लंबी कतारें लगी हुयी हैं। हालांकि प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने में टेस्टिंग सेंटरों को वाहनों की अच्छी तरह से जांच भी करनी चाहिये। देश में आम लोगों की यह फितरत रही है कि वो मामूली काम में भी वाहन का उपयोग करते हैं और प्रायः पब्लिक ट्रांसपोर्ट से परहेज करते रहे हैं। हाल की सख्ती के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग में एकाएक वृद्धी दिखी है। इसके अलावा सायकिल के उपयोग की भी हम उम्मीद कर सकते हैं। जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिये अच्छा होगा।

> जब हौलैंड के राष्ट्रपति सायकल से अपने कार्यालय जाते हैं, तो हम भारतीय उनकी तारीफ करते हैं, सोशल मीडिया में उनकी तस्वीर भी चस्पा करते हैं, पर खुद अपनी बारी आये तो हम सायकिल से तौबा कर लेते हैं। वहीं ट्रैफिक नियमों की सख्ती के दूरगामी और सुखद परिणाम मिलेंगे। भय से ही हेलमेट पहनने, और खतरनाक ड्राइविंग से परहेज करने से दुर्घटनाओं में दुखद मौत की संख्या में कमी आयेगी। इस पहल का सबसे ज्यादा लाभ पर्यावरण को होगा। निजी वाहनों के उपयोग में कमी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग से सड़कों पर अनावश्यक वाहन कम होंगे जिससे प्रदूषण का स्तर कम होगा।

याद किजिये दो साल पहले जब दिल्ली में प्रायोगिक तौर पर वनवे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गयी थी, तो उन दो तीन दिनों में ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एकाएक घट गया था। आज अगर सरकार ट्रैफिक नियमों को सख्त कर उसे लागू करने का प्रयास कर रही है तो यह आम जन के लिये ही है। हर साल पर्व त्यौहारों के मौसम के बाद सिर्फ राजधानी रांची की सड़कों पर ही पांच हजार दो पहिया वाहन बढ़ जाते हैं। आम भारतीय के लिये आज भी कार और एसयूवी जरूरत से ज्यादा वैभव और प्रदर्शन की चीज है। इस मानसिकता के कारण भी देश में चारपहिया वाहनों की संख्या साल दर साल बढती चली गयी। इतनी बड़ी संख्या में जब ये वाहन सड़कों पर उतरते हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन प्रायः नहीं किया जाता। इस कारण से दुर्घटना, रोड रेज की वारदातें तो होती ही हैं, साथ ही इन वाहनों से निकलने वाला धुंआ आखिर हमारे पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचाता है।

दुनिया भर के आंकड़ों को अगर हम तुलनात्मक तौर पर देखें तो सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट भारत की सड़कों पर होती हैं, इन दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा लोग मौत का शिकार भारत में होते हैं।

दो साल पुराने आंक्ड़े बताते हैं कि, रांची में जब महज 2800 सौ डीजल ऑटों के परमिट थे उस वक्त भी यहां की सड़कों पर पांच हजार से ज्यादा ऑटो चल रहे थे। जो ध्वनि प्रदूषण फैलाने के साथ ही ट्रैफिक जाम और प्रदूषण के कारण भी हैं। आज यह आंकड़ा और भी बढ़ गया होगा?अभी देश में तकरीबन 7 करोड़ से ज्यादा कारें हैं और इनका सड़कों पर आना ध्वनि के साथ ही वायू प्रदूषण को बढाता है। बढती आबादी, बेरोजगारी अपनी जगह है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि हम भारतीय संयम से वाहनों के उपयोग और ट्रैफिक नियमों के पालन में फिसड्डी हैं। अब अगर सरकार हमारी यह गलत आदत सुधारना चाहती है तो हमें इस पर क्षुब्ध होने के बजाय इसका स्वागत करना चाहिये।

एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक का अंत मोदी के लिए बड़ी चुनौती

आदिति फडणीस

जून 2018 में जब नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अप्रत्याशित घोषणा की कि भारत सन 2022 तक एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल समाप्त करने की नीति अपनाएगा तो लोग हंस रहे थे। इसकी वजह भी थी। दरअसल एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को देखते हुए प्रधानमंत्री ऐसा सोच भी कैसे सकते थे? कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की लेकिन ज्यादातर मामलों में ये निरर्थक साबित हुए।

गत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन मोदी ने अपने भाषण में दोहराया कि एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का प्रयोग बंद किया जाएगा। इसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए लेकिन यह कहना जितना आसान है, इस पर अमल करना उतना ही मुश्किल।देश में प्लास्टिक के दो पहलू हैं। एक ओर विनिर्माण समेत सरकार की पहलों और प्रयासों के कारण वाहन क्षेत्र और आधुनिक सिंचाई आदि में प्लास्टिक उत्पादों के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर एक बार प्रयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक का बढ़ता प्रयोग और उससे जुड़े प्रदूषण को लेकर बढ़ती जागरूकता के बीच राजनीतिक हितों के चलते उसका बचाव किया जा रहा है। कारण यह कि लागत की दृष्टि से संवेदनशील बाजार है जहां प्रमुख रूप से असंगठित और छोटे कारोबारी शामिल हैं।देश और विदेश में प्लास्टिक से जुड़ी अर्थव्यवस्था किस प्रकार बढ़ी और विकसित हुई, इस बारे में विद्वान चीजों को स्पष्ट कर चुके हैं। यह बात प्लास्टिक के इस्तेमाल के बाद उस पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, इससे पता चलती है। पश्चिम में पॉलिमर और अन्य उत्पादों का प्रसार सन 1950 के दशक में आरंभ हुआ जब प्लास्टिक कचरे के प्रयोग के बाद की चुनौतियों को लेकर जागरूकता अधिक नहीं थी। परंतु हमारे देश में प्लास्टिक उद्योग की वृद्धि उस समय हुई जब सन 1970 और 1980 के दशक में इसके पर्यावरण प्रभाव को लेकर जागरूकता बढऩे लगी थी। इसलिए इस उद्योग में वृद्धि के साथ-साथ इन उत्पादों का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों की प्रतिष्ठा का जोखिम भी बढऩे लगा। बहरहाल, औपचारिक पुनर्चक्रण उद्योग भी इससे कदमताल नहीं कर सका क्योंकि किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं जुड़ा है। सबसे उल्लेखनीय आंकड़े दिल्ली के पैकेजिंग सामग्री क्षेत्र से मिलते हैं जो प्लास्टिक उद्योग का सबसे लोकप्रिय क्षेत्र भी है। स्वयंसेवी संगठनों के शोध के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 660 ऐसी कंपनियां हैं जो एकल प्रयोग वाला प्लास्टिक बनाती हैं। जबकि 1,242 कंपनियां प्लास्टिक का आयात और निर्यात करती हैं। केवल 272 ऐसी संस्थाएं हैं जो औपचारिक रूप से प्लास्टिक के पुनर्चक्रण और पुनःप्रसंस्करण से जुड़ी हैं।दुनिया की जो 10 नदियां विश्व का 90 प्रतिशत प्लास्टिक समुद्र तक ले जाती हैं, वे सभी भारत में बहती हैं। इनमें सिंधु, गंगा और

ब्रह्मपुत्र शामिल हैं। जनवरी 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के शहर हर रोज 15,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न कर रहे थे। 10 टन प्रति ट्रक के हिसाब से यह कचरा 1,500 ट्रक के बराबर था। इसमें से 9,000 टन प्लास्टिक का संग्रह कर उसका पुनर्चक्रण कर लिया जाता जबकि शेष 6,000 टन कचरा यानी 600 ट्रक कचरा नालियों, गलियों या कूड़े के ढेर पर पड़ा रहता है। प्लास्टिक कचरे का 66 फीसदी पॉलिबैग या पाउच के रूप में होता है जिनका इस्तेमाल खाना पैक करने में किया जाता है। देश में सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा दिल्ली में उत्पन्न होता है। इसके बाद कोलकाता और अहमदाबाद आते हैं। सन 2017 में लोकसभा में प्लास्टिक कचरे से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए तत्कालीन पर्यावरण राज्य मंत्री महेश शर्मा ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि ये तीनों शहर एक दिन में 4,059 टन प्लास्टिक उत्पन्न करते हैं। प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में सबसे बड़ी बाधा है कचरे को अलग-अलग न करना। शहर-शहर का भी अंतर है। सूरत में शहर के कुल कचरे में प्लास्टिक 12.47 प्रतिशत है जबकि चंडीगढ़ में केवल 3.1 प्रतिशत। प्लास्टिक की बोतलें आसानी से पुनर्चक्रित की जा सकती हैं लेकिन कचरा बीनने वालों को प्लास्टिक की थैली एकत्रित करने के लिए अलग से कोई प्रोत्साहन नहीं है। एक किलो प्लास्टिक थैली एकत्रित करने में बहुत अधिक मेहनत लगती है जबकि बदले में कुछ नहीं मिलता। नतीजा, इसे लेकर सुस्ती बरती जाती है।इस बीच, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के छोटे विनिर्माता विरोध जता रहे हैं।

महाराष्ट्र प्लास्टिक ऐंड थर्मोकोल प्रोडक्ट्स ने मार्च 2018 में एक अधिसूचना जारी की जिसके तहत प्लास्टिक बैग और कटलरी के साथ-साथ प्लास्टिक की पैकिंग पर रोक लगाई गई। परंतु इस अधिसूचना के बाद बिना विकल्प सुझाए एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक के निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं पर अत्यधिक कड़ाई होने लगी। यह प्रतिबंध फेंके जाने वाले प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर था। इसमें छोटी बोतल, बैग, प्लेट, कटलरी, स्ट्रॉ आदि शामिल थे। इनके निर्माण और बिक्री पर जुर्माना और तीन महीने तक की जेल का प्रावधान था। प्रतिबंध के पहले सप्ताह में 300 से अधिक प्लास्टिक बैग बनाने वाले निर्माताओं को बंदी का सामना करना पड़ा। इससे हजारों लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए।

प्लास्टिक निर्माताओं, दूध उत्पादकों, छोटे कारोबारियों, पेप्सी और कोका-कोला जैसी कंपनियों तथा एमेजॉन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के अनुरोध पर सरकार ने नियम शिथिल कर दिए, जिससे उन्हें विकल्प तलाशने का समय मिल गया। एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक को खत्म करना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की असली परीक्षा होगी। क्या मोदी एकल प्रयोग प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने के लिए सबों को मना पाएंगे?

विश्व पर्यावरण को बचाने, खेती योग्य भूमि के संरक्षण और ऊसर होने से रोकने , जलवायू के संरक्षण के उद्देश्य से बना है दुनिया भर के देशों का संगठन कान्फ्रेंस ऑफ पार्टीज

कॉप 14 की सफलता से बचेगा विश्व पर्यावरण

भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी) के पार्टियों (कॉप-14) के 14वें सत्र की मेजबानी कर रहा है। भारत में यह सम्मेलन 02 सितंबर से 13 सितंबर तक आयोजित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि इस शिखर सम्मेलन में लगभग 200 देश शामिल हो रहे हैं तथा 3,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार अगले 10 साल में 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जाएगा। इससे करीब 75 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस सम्मेलन का प्रयास खराब जमीन को उपजाऊ जमीन में बदलने का प्रयास है। यहां कई देशों के वैज्ञानिक अपने-अपने इनोवेशन की भी प्रदर्शनी करेंगे।

कॉप का प्रमुख कार्य

कॉप COP) यानि ***कान्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज*** का प्रमुख कार्य उन रिपोर्टों की समीक्षा करना है जो सदस्य देश अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के संदर्भ में बैठक के दौरान रखते हैं। कॉप के इस सम्मेलन में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय, विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र, निजी क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय एवं स्वयंसेवी संगठन और मीडिया के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

खेती के योग्य बनाने हेतु यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के साथ समझौता

केंद्र सरकार बंजर जमीन को खेती के योग्य बनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के साथ समझौता भी करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आगे कहा कि हमारी सरकार नई दिल्ली डिक्लेरेशन में बताए गए नियम एवं कायदों के मुताबिक इस काम को आगे बढ़ाएंगे। यूएनसीसीडी (कॉप-14) में 200 देश भाग लेंगे। प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार, यूएनसीसीडी (कॉप-14) में 200 देश भाग लेंगे। रियो डी जेनेरियो (ब्राज़ील) के बाद पहली बार इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। भारत अगले दो साल तक यूएन सीसीडी का अध्यक्ष रहेगा। इस सम्मेलन में लगभग 100 देशों के मंत्री भी आएंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में 09 सितंबर और 10 सितंबर को सभी देशों के मंत्री शामिल होंगे. यह सम्मेलन ग्रेटर नोएडा में होगा।

देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30 प्रतिशत प्रभावित

पर्यावरण मंत्री के अनुसार जमीन के क्षरण से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30 प्रतिशत प्रभावित हो रहा है। भारत ने पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 2015 में स्वैच्छिक रूप से बोन चुनौती पर स्वीकृति दी थी। बोन चुनौती एक वैश्विक प्रयास है। भारत ने कहा था कि 13 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर साल 2020 तक और अतिरिक्त 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर साल 2030 तक वनस्पतियां उगाई जायेंगी। इसमें मदद हेतु देहरादून में सेंटर ऑफ एक्सक्सेल की स्थापना भी की जाएगी।

कॉप क्या है?,

यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क (यूएनएफसीसीसी) सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। इस निकाय के तहत विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को सम्मेलन में शामिल किया गया है। यह प्रत्येक साल अपने सत्र आयोजित करता है। कॉप, सम्मेलन के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्णय लेता है और नियमित रूप से इन प्रावधानों के कार्यान्वयन की परीक्षण करता है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क (यूएनएफसीसीसी):

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क (यूएनएफसीसीसी) एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसका मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। यह समझौता जून 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। इस समझौते पर विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च 1994 को इसे लागू किया गया था।

यूएनएफसीसीसी की वार्षिक बैठक का आयोजन साल 1995 से लगातार किया जाता है। यूएनएफसीसीसी की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (कॉप) के नाम से भी जाना जाता है।14वें कॉप की बैठक में सदस्य देशों की सर्वसम्मति बहुत कुछ तय करेगी।

मिट्टी से पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं : जग्गी वासुदेव

मिट्टी की दशा इतनी खराब हो गई है कि हम जो अन्न, सब्जियां, फल उगा रहे हैं, उनके पोषक तत्व विनाशकारी ढंग से कम होते चले जा रहे हैं। विशेष रूप से भारतीय सब्जियों में तो पिछले 25 सालों में पोषक तत्वों में 30% तक की गिरावट आई है। विश्व में हर तरफ डॉक्टर लोगों को मांसाहारी भोजन से शाकाहारी भोजन की तरफ मुड़ने को कह रहे हैं पर भारत में, डॉक्टर हमें मांस खाने की सलाह दे रहे हैं। क्यों? जब सारी दुनिया यह प्रयास कर रही है कि लोग मांसाहार छोड़ कर शाकाहारी जीवन का रास्ता अपनाएं तो हम, जो मुख्यतः एक शाकाहारी देश हैं, मांस की ओर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे शाकाहारी खाद्य पदार्थो में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं हैं। और यह बस इसलिए है क्योंकि हमने अपनी मिट्टी की परवाह नहीं की है, उसे संभाला नहीं है। मिट्टी के सूक्ष्म पोषक तत्व इतने नाटकीय ढंग से कम हो गए हैं कि हमारे 3 वर्ष से कम उम्र के लगभग 70% बच्चे कुपोषित हैं, उनमें स्वस्थ रक्त की कमी है। अगर आप जंगल में जाएं और वहां की मिट्टी की जांच करें तो वह जीवन से भरपूर, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली मिलेगी। मिट्टी ऐसी ही होनी चाहिए। अगर मिट्टी की शक्ति कम हो जाती है, तो हमारे शरीर भी कमजोर पड़ जाएंगे-सिर्फ पोषण की दृष्टि से ही नहीं पर अत्यंत मूल रूप से। इसका अर्थ यह है कि हम जो अगली पीढ़ी पैदा करेंगे, वह हमसे कम शक्तिशाली होगी। यह तो मानवता के प्रति अपराध है। हमारी अगली पीढ़ी हमसे बेहतर होनी चाहिए। अगर वह हमसे कम है, तो इसका अर्थ यही है कि हमने मूल रूप से कुछ बहुत गलत किया है। यह भारत में बहुत बड़े रूप में हो रहा है क्योंकि हमारे देश की मिट्टी अपनी शक्ति खो रही है।

चलों पृथ्वी को बचाएं: सीए गुरप्रीति कौर रांची

अभी भी समय है कि हम, हमारा समाज और हमारी सरकारें ये सुनिश्चित करें कि हर परिवार कम-से-कम एक पेड़ लगाएं और उसे बड़ा करे। वर्षा के पानी का प्रत्येक घर, स्कूल, ऑफिसों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि में संचयन की व्यवस्था हो। तालाबों, ताल-तलैयों और विभिन्न जलस्रेतों का ईमानदारी से परिरक्षण हो। जितना संभव हो पुराने हरे-भरे वृक्षों को बचाया जाए। सरकारें कार लॉबी के दबाव से मुक्त होकर प्राइवेट कारों और टैक्सियों की जगह सार्वजनिक परिवहन की अधिकतम उपयोग की सुविधा जनसाधारण को देना सुनिश्चित करें। इन उपायों से यहां के मौसम और बढ़ती गर्मी से जरूर राहत मिलेगी। कहने का आशय है कि पर्यावरण को लेकर संजीदा होना होगा लोगों को।

उत्तरी ध्रुवों पर भी ग्लेशियरों के पिघलने की चिंताजनक खबरों के बीच हिमालय के पिघलते ग्लेशियर भविष्य के लिये खतरे का संकेत दे रहे हैं

चिंतन खतरे की घंटी है लगातार पिघलते हिमालय के ग्लेशियर

- ग्लेशियरों के पिघलने से बाढ़ और खतरनाक कृत्रिम झीलों के बनने का है खतरा
- नेपाल के पोखरा में ऐसी झीलों के कारण ही आयी थी बाढ

मुकुल व्यास

गर्म तापमान ने पिछले 40 वर्षों के दौरान हिमालय के ग्लेशियरों की करीब एक चौथाई बर्फ को पिघला दिया है। एंटार्कटिक और आर्कटिक के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा बर्फ भंडार हिमालय के पर्वतों में पाया जाता है। इस दुर्गम क्षेत्र के अब तक के पहले संपूर्ण अध्ययन से पता चलता है कि 2000 से 2016 तक हिमालय के ग्लेशियर अपनी अरबों टन बर्फ गंवा चुके हैं। पिघलने वाली बर्फ की मात्रा 1975 से 2000 तक पिघली बर्फ से दोगुनी है।कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लामोंट-डोहर्टी अर्थ ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिक और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक जोशुआ मारेर ने कहा कि चालीस वर्ष की अवधि में हिमालय के ग्लेशियरों का यह पहला व्यापक अध्ययन है। नया अध्ययन 'साइंस एडवांसेस' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। आंकड़ों से पता चलता है कि इस क्षेत्र के तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इस अध्ययन के सह-लेखक जोएर्ग स्काफर का कहना है कि एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। हिमालय के ग्लेशियरों में बर्फ क्षति तापमान वृद्धि से जुड़ी हुई है, इस बात का खुलासा उपग्रहों द्वारा लिए गए चित्रों से हुआ है। अमेरिकी के एच-9 हेक्सागॉन सैनिक उपग्रहों ने 1973 से 1980 के बीच इस क्षेत्र के कई चित्र लिए थे। इन उपग्रहों द्वारा लिए गए चित्रों को सार्वजनिक किए जाने के बाद वैज्ञानिकों ने इन चित्रों को 3डी मॉडलों में बदला। इन मॉडलों की तुलना अत्याधुनिक उपग्रहों द्वारा हाल में लिए गए चित्रों से की गई। इससे वैज्ञानिकों को 650 ग्लेशियरों में पिछले 40 वर्षों के दौरान आए परिवर्तनों के अध्ययन का मौका मिला।गौरतलब है कि ग्रीनलैंड की तुलना में हिमालय के ग्लेशियरों का बहुत कम अध्ययन हुआ है क्योंकि यह दुनिया के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से है। मारेर के अनुसार भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से यहां रिसर्च करना बहुत कठिन है। हिमालय की पर्वतमाला करीब 1500 मील लंबी है। इस क्षेत्र की बर्फ गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और अन्य विराट नदियों की

स्रोत है। इस अध्ययन में पामीर और हिंदुकुश जैसी निकटवर्ती पर्वतमालाओं को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन नए अध्ययनों से पता चलता है कि वहां भी इसी तरह से बर्फ पिघल रही है। बर्फ के पिघलने का अर्थ यह है कि स्थिर ग्लेशियरों की तुलना में जल प्रवाह बढ़ेगा जिसके फलस्वरूप बाढ़ें आएंगी। इसके अलावा इससे अनेक नई झीलें बनेंगी और वे झीलें भी आकस्मिक विनाशकारी बाढ़ों को जन्म दे सकती हैं। नेपाल में पोखरा के आसपास के गांवों में मई 2012 में आई इसी तरह की एक बाढ़ में 60 से अधिक लोग मारे गए थे।

क्विंसी नेपाल के खुंबू ग्लेशियर में एवरड्रिल नामक रिसर्च प्रॉजेक्ट चला रहे हैं। प्रॉजेक्ट के तहत ग्लेशियर में काफी गहराई तक ड्रिलिंग की जाती है और बर्फ के तापमान पर निगरानी रखी जाती है। एवरड्रिल के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्लेशियर अंदर से भी गर्म हो रहे हैं। ग्लोबल वॉर्मिंग ग्लेशियर युक्त ठंडे पर्वतों को एक सदी के अंदर चट्टानों में बदल देगी। हिमालय के ग्लेशियरों के बारे में किए गए एक पांच वर्षीय अध्ययन में कहा गया है कि यदि साल 2100 तक खनिज ईंधनों के उत्सर्जन में समुचित कटौती नहीं हुई तो हिमालय अपनी 66 प्रतिशत बर्फ खो बैठेगा। इस अध्ययन में 350 रिसर्चरों ने योगदान किया है। कोलंबिया यूनिर्विसटी के वैज्ञानिक स्काफर ने कहा कि भीषण गर्मी और हिमालय से घटते जल प्रवाह की वजह से एशिया एक बड़ी विपदा की स्थिति का सामना कर रहा है। इन खतरों से बचने के लिए सामाजिक जागरूकता के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के स्वरूप में बड़े बदलाव लाने होंगे।

झारखण्ड के कारीगरों के हस्तशिप अब ऑनलाइन बिकेगे : मुख्यमंत्री

रांची :मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के कारीगरों, हस्तकरघा, बुनकरों और शिल्पकारों में कौशल की कमी नही है. झारखंड के कण-कण में कला का वास है। झारखंड के शिल्पकार, हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों के लिए आज खुशी का दिन है। मुझे यकीन है कि फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ने से झारखंड के शिल्प और पारंपरिक कौशल को राष्ट्रीय बाजार का लाभ मिलेगा। यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लोगों को पूरे झारखंड के शिल्प, पारंपरिक कौशल और ज्ञान के साथ एकजुट करेगा. झारखंड सरकार व फ्लिपकार्ट के साथ हुए इस समझौते से राज्य के कलाकार लाभान्वित होंगे. उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने झारखंड मंत्रालय के सभा कक्ष में झारखण्ड सरकार और फ्लिपकार्ट के बीच हुए समझौता हस्ताक्षर (एमओयू) के बाद क-हीं.कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ई-कॉमर्स के पटल पर लाने का हुआ आगाज मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के हजारों कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ई-कॉमर्स के पटल पर लाने की तैयारी हो चुकी है. राज्य सरकार द्वारा बांस, खादी और हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने व ऐसे कलाकारों के उत्पाद को बदलते वक्त एवं समय की मांग को देखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग के वृहद बाजार में उतारने के लिए झारखण्ड सरकार और फ्लिपकार्ट ग्रुप ने ''समर्थ'' समझौता पर हस्ताक्षर किया।

नया फसल और नए फल की पूजा करते हैं और प्रसाद स्वरूप खाते हैं नवा खावा पर्व में

ईष्टदेव,पूर्वज को करता है याद, अन्न बन जाता है प्रसाद

सिदाम महतो

रांची/बुण्डू :किसान अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता है।उसको पता होता है, मेहनत के बगैर कुछ हासिल नही होता है।फिर भी वह उपरवाले की मेहरबानी को भूलता नहीं है।समय पर बारिश,समय पर धूप, फसल के लिए अनुकूल परिस्थिति तो वरदान स्वरूप मिलती है।इस वरदान के प्रति किसान हमेशा ही कृतज्ञ रहता है।

नावा खावा(नया अन्न खाना) के अवसर पर किसान अपने ईष्टदेव, अपने पूर्वज के प्रति आभार प्रकट करता है। झारखण्ड के सभी किसानो के बीच बांटकर खाने की परम्परा है, ऐसे संस्कार हैं।क्षेत्र के अनुसार इसके अलग -अलग नाम हैं। पंचपरगना क्षेत्र में इसे नावा खावा के नाम से जानते हैं। भादो महीने के शुक्ल पक्ष के किसी अनुकूल दिन पर (अपने-अपने सुविधा अनुसार) इस नेग(नियम) का पालन किया जाता है। उस समय मैदानी धान(गोड़ा धान) लगभग पक जाता है। उस नए धान को कूटकर चावल बनाया जाता है। उसी चावल का नए मिट्टी के बर्तन में गुड़ भात(चावल) बनता है। सबसे पहले उस भात को अपने ईष्टदेव को चढ़ाया जाता है, अपने वंश के पूर्वजों को चढ़ाया जाता है। फिर परिवार के सदस्य मिल बांटकर गुड़-भात को ग्रहण करते हैं।ऐसी मान्यता है कि अपने ईष्टदेव को,अपने पूर्वज को नया अन्न दिए बिना कोई भी व्यक्ति कहीं

भी नया अन्न ग्रहण नही करता है। किसान भीष्मदेव महतो बताते हैं कि जाति विशेष, वंश(गौत्र) के अनुसार अपने-अपने ईष्टदेव हैं।हमारे ईष्टदेव हैं-धर्म,बड़ पहाड़, ग्राम देवता,गाय, गोरैया, भैंस गोरैया, लिलौरी, बानसा, घाटवार, गौसाई राय। सभी इष्टदेवता के नाम नया अन्न देते हैं। इस दिन हम बूढ़ा-बूढी(अपने पूर्वज-दादा परदादा आदि) को याद करते हैं।पहले तो एक वंश के सभी परिवार एक साथ नावा खावा करते थे।आजकल सब परिवार अलग-अलग करते हैं।किसान महिंदर महतो बताते हैं कि कभी-कभी जाने -अंजाने कीड़े-मकोड़े घर में घुस जाते हैं। उन सबको भी नावा खावा के अवसर पर याद करते हैं।

नावा खावा क्यों करते हैं?

इस सवाल के जवाब में कृषक नकुल महतो बतातें हैं कि, नया फसल और नए फल की हमलोग पूजा करते हैं और प्रसाद स्वरूप खाते हैं। हमारे पूर्वज ही ऐसा करते आए हैं इसलिए हमलोग भी करते हैं। वह आगे बताते हैं कि चैत्र महीना के संक्रांति में भी जब आम फल आने लगता है तो उस समय आम फल की पूजा करते हैं।बिना

आम फल की पूजा किए हम आम नही खाते। मनसा पर्व में हम मकई को मनसा माँ को याद करके प्रसाद स्वरूप खाते हैं।इससे पहले मकई खाने की मनाही है।आजकल बाजार में मकई आते ही लोग खाने लग जा रहे हैं।

.....पेज 1 का शेष **धान की परती भूमि**

परीक्षण किये गये. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित 61 अनुमोदित किस्मों का प्रजनक बीज विभिन्न केन्द्रों को आवंटित किया गया. देश में 84.76 क्विंटल प्रजनक बीज कि मांग की तुलना में 256.32 क्विंटल प्रजनक बीज तैयार किया गया.

डॉ राय ने बताया कि परियोजना के तहत 14 राज्यों के 63 जिलों में सिंचित एवं बारानी अवस्था में राई पर 1671 तथा सरसों पर 409 अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण किया गया. सिंचित अवस्था में राई - सरसों कि अधिकतम पैदावार 2754 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरियाणा में प्राप्त हुआ. जबकि बारानी अवस्था में अधिकतम औसत पैदावार 1590 क्विंटल प्रति हेक्टेयर राजस्थान में दर्ज किया गया. देश में इसके खाद्य तेल की भारी मांग है . इस मांग को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष करीब 80-85 हजार करोड़ लागत खाद्य तेल का आयात किया जाता है.

इस अवसर पर आईसीआर सहायक महानिदेशक डॉ एसके झा, बीएयू निदेशक अनुसंधान डॉ डीएन सिंह तथा आईसीआर शासी निकाय के किसान प्रतिनिधि एके सिंह ने भी अपने विचारों को रखा.

झारखण्ड में मसूर-सरसों की अंतरवर्ती खेती की अनुशंसा आइसीएआर के सहायक महानिदेशक (बीज) डॉ डीके यादव की अध्यक्षता में आयोजित समापन सत्र में राई एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान के वैज्ञानिकों- डॉ एचके सिंह, डॉ ओपी प्रेमी, डॉ पुष्प शर्मा, डॉ अनुभूति शर्मा, डॉ अर्चना अनोखे, डॉ पीडी मीणा, डॉ भागीरथ राम, डॉ एके शर्मा और डॉ पीके राय ने बैठक में वैज्ञानिक अनुशंसाओं को रखा. बैठक में परियोजना के अंतर्गत विकसित किस्मों की आणविक फिंगर प्रिंटिंग हेतु सरसों अनुसंधान निदेशालय में आधुनिक सुविधासंपन्न प्रयोगशाला का विकास करने तथा अच्छी उत्पादन क्षमतावाले राई-सरसों के 15 जनन द्रव्यों के एडवांस्ड किस्मों को जांच हेतु अनुमोदित किया गया.

शोध के आधार पर झारखण्ड में बेहतर उत्पादकता के लिए मसूर-सरसों की अंतरवर्ती खेती की अनुशंसा की गयी. बैठक में बताया गया कि विभिन्न फसल प्रणालियों में मूंग-सरसों प्रणाली पंतनगर (उत्तरखंड) एवं मुरैना (मध्यप्रदेश) केन्द्रों पर ज्यादा उत्पादन देने में सफल रही. सरसों को 60 ७ 60 सेंमी की दूरी पर रोपण करने से नई दिल्ली, नागपुर एवं वाराणसी में क्रमशः 10.2, 45.8 एवं 27.2 प्रतिशत अधिक उत्पादन मिला. सरसों के 12 जनन द्रव्य सफ़ेद रोली रोग के प्रति प्रतिरोधक पाए गए, जिन्हें इस वर्ष प्रांकुर अवस्था में जांच हेतु अनुशंसित किया गया. देश भर में चल रहे प्रयोगों के दौरान सरसों का एक जनन द्रव्य प्रांकुर अवस्था पर अधिक तापमान और नमी तनाव सहनता हेतु प्रभावी पाया गया. दो जनन द्रव्य पकाव के समय अधिक तापमान सहन हेतु प्रभावी पाए गए.

कार्यक्रम का संचालन श्रीमती शशि सिंह और धन्यवाद ज्ञापन आयोजन सचिव डॉ जेडए हैदर ने दिया। बैठक में पूरे देश में राई-सरसों का क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने की तौर-तरीकों पर वैज्ञानिकों ने तीन दिनों तक चर्चा की गई. इसमें 17 राज्यों के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और निजी उद्योग क्षेत्रों के 130 वैज्ञानिकों ने भाग लिया. मौके पर डॉ एमएस यादव, डॉ एमपी सिन्हा, डॉ ए वदूद, प्रो डीके रूसिया, डॉ सोहन राम, डॉ डीके शाही और डॉ अरुण कुमार भी मौजूद थे।

एन के क्षेत्र में सीसीएल ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ

खेल और विकास प्रथम प्राथमिकता- सांसद राँची

सीसीएल द्वारा अपने निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत आज 06 सितम्बर को सीसीएल के एन.के. क्षेत्र स्थित 'डकरा स्टेडियम' में ''सीसीएल ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता'' का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय सांसद, रांची श्री संजय सेठ, विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक, कांके, डॉ. जीतूचरण राम, सीसीएल के सीएमडी श्री गोपाल सिंह, महाप्रबंधक (एन के क्षेत्र) श्री एम के राव उपस्थित थे । मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियो ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें बेहतर खेलने के लिए प्रेरित किया। अतिथियों का स्वागत पारंपरिक ढंग से स्कूली बच्चों ने किया ।

धनबाद –जलशक्ति अभियान के तहत धनबाद में वृक्षारोपण शुरू। शहर के 35 किलोमीटर सड़क पर लगेगा एक लाख पेड़। मेयर शेखर अग्रवाल ,उपायुक्त अमित कुमार के नेतृत्व में शुरू हुई अभियान। मेंमको मोड़ से शुरू हुई अभियान। 15 सितंबर तक चलेगा अभियान।

मुख्यमंत्री ने सभी को दी पोषण महोत्सव एवं करम की शुभकामनाएं

रांची :मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर के जोन-6 स्थित बिरसानगर में आयोजित पोषण महोत्सव में सबों को करम पर्व की शुभकामनायें दी और कहा कि झारखण्ड में पोषण महोत्सव पूरे वर्ष मनाया जायेगा।सिंहभूम समेत पूरे राज्य की गर्भवती महिलाओं का निबंधन करें। राज्य की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 6 हजार रुपये मुहैया कराया जाता है, ताकि वे पौष्टिक भोजन इस अवधि में ले सकें।

विद्यालय के बच्चों के बीच में चित्रांकन प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

रामकृष्ण विद्या निकेतन में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान

राँची / गढ़गाँव : स्वामी विवेकानंद मिशन के रामकृष्ण विद्या निकेतन विद्यालय परिसर में पावर ग्रिड बेड़ो द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत विद्यालय के बच्चों के बीच में चित्रांकन प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया` इसमें बच्चों को दो ग्रुप में बांटा गया कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के बीच में चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजन किया गया एवं कक्षा तीन से पांच तक के बच्चों के बीच में हिंदी एवं अंग्रेजी में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ! इस कार्यक्रम में बच्चों ने काफी उत्साह पूर्वक प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी निभाई` कार्यक्रम में कक्षा एक से पांच तक के बच्चों ने चित्रांकन और भाषण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय ,तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त कर के बच्चों ने एक मिसाल कायम किये ! पावर ग्रिड के जीएम एमआर पति कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को यह भी बताया कि किस तरह से वे अपना पर्सनल साफ-सफाई पर ध्यान देंगे ! क्योंकि आज जरूरत है अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के साथ-साथ अपने आपको भी स्वच्छ रखें ताकि बीमारी नहीं हो और न हीं उन्हें इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ! उन्होंने बच्चों को बताया की हलड की रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति औसतन 6500 रुपया पैसा सालाना अपने स्वास्थ सम्बन्धी में खर्च करता है ! साथ में पौधारोपण भी किया गया जिसमे पावर ग्रिड के चीफ मैनेजर राजीव रंजन ने सन्देश दिया की पौधों के रोपण करने से इसके तुरंत में तो फायदे नहीं मिलते हैं, लेकिन जब यही पौधे बड़े होकर पेड़ का रूप ले लेते हैं तो यह भरपूर मात्रा में हमें ऑक्सीजन देते हैं जिन्हें हम प्राणवायु कहते हैं और यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं ! पौधारोपण से यह फायदा होगा की हमारे परिवेश में जो दूषित हवा होते है उसे पेड़ पौधे अपने में शोषित करके हमें वातावरण शुद्ध देती हैं । उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को ग्रिड के जीएम एमआर पति के द्वारा पुरस्कृत किया गया ! मौके पर विद्यालय की प्राचार्या विनीता कुमारी ने पावर ग्रिड के इस जन अभियान तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये सफल कार्यक्रम की सराहना की तथा धन्यवाद् दिया ! अंत में कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती पूनम करण द्वारा संपन्न हुआ, कार्यक्रम को सफल बनाने में रोहित श्रीवास्तव ,प्रशांत बारीक, अभिमन्यु मिरदा, पीएस रजक,जय नायक एवं पावर ग्रिड के सहकर्मी तथा विद्यालय के शिक्षको का भरपूर सहयोग रहा।

पटमदा की बारुबेड़ा डूंगरी में सफल जल संचयन

- गोद में बसे चार गांवों का भू-जल स्तर होगा रिचार्ज
- ट्रेंच खोदने के लिए प्रभाकर कोड़ा ने 6 बीघा रैयती डुंगरी जमीन दी है।
- विरान डुंगरी पर सरकार खोद रही स्टैजर्ड ट्रंच।

जमशेदपुर लौहनगरी से करीब 40 किमी की दूरी पर अवस्थित है बारुबेड़ा डुंगरी। सड़क के किनारे से इसे आप देखेंगे तो कुलू-मनाली की वादियों सा यहां नजारा दिखेगा। डुंगरी यानी छोटी पहाड़ी। मुरुम की यह पहाड़ी करीब 125 एकड़ में फैली है। डुंगरी पर हरी घास इस तरह से उगी हुई है मानो किसी पार्क की लैंडस्केपिंग कर उसकी छंटाई की गई है। डुंगरी के दक्षिण और पश्चिम के नीचले इलाकों में गांव और खेत हैं। गांव के मवेशी इस डुंगरी पर ही हरे-हरे मुलायम घास चरने आते हैं। गर्मी में जहां गांव के लोग यहां देर शाम तक बैठ कर ठंडी हवा खाते हैं किन्तु बरसात में इससे वर्षा का पानी इतनी तेजी से खेत और गांव में उतरता है कि कई बार फसल और गांव में नुकसान हो जाता है। बारिस का पानी जितनी तेजी से खेत में उतरता है उतनी ही तेजी से वह नाले होते हुए गायब भी हो जाता है। नतीजा बारुबेडा डुंगरी की गोद में बसे बांगुरदा, कुमीर और काशमार पंचायत वाले इलाकों में साल में एक ही फसल हो पाती है। नहर की सुविधा नहीं है और किसान पूरी तरह से बारिश के पानी पर कृषि कार्य के लिए आश्रित है।

पटमदा प्रखंड कार्यालय से 13 किलोमीटर की दूरी पर बारूबेड़ा डूंगरी में जल संरक्षण एवं संचयन के तहत तीन पंचायत(बांगुरदा, कुमीर एवं काश्मार) में कुल 125 एकड़ परती एवं डुंगरी जमीन में सरकार के विशिष्ट कार्य योजना के तहत जल संचयन के लिए टीसीबी का निर्माण कराया गया है।

भूजल स्तर गिरने से चिंतित थे ग्रामीण

खेती और इंसानी जरुरतों के चलते क्षेत्र में भूजल का दोहन बढ़ा है और नतीजा बारुबेड़ा डुगरी के आस-पास के गांवों और खेतों में जहां 10 साल पहले तक 20-30 फुट की गहरायी पर कु एं एवं बोरिंग का पानी मिल जाता था अब उसके लिए 50 से 80 फीट

गहरायी पर बोरिंग करनी पड़ती है।क्षेत्र के जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए मुरुम पहाड़ी बारुडीह डुंगरी अब जरिया बनेगा। पटमदा के प्रखंड विकास पदाधिकारी शंकराचार्य आचार्य ने कहा, कि डुंगरी पर काफी बारिश होती है।

उक्त योजना मनरेगा अंतर्गत संचालित है, प्रत्येक कार्य योजना के लिए रोजगार गारंटी योजना के तहत लगभग 198 मजदूरों को कार्य दिया जा रहा है जिससे मनरेगा के तहत मजदूरों को निकटवर्ती स्थानों में कार्य मिल रहा है एवं पलायन पर भी रोक लगा है। प्रति एकड़ लगभग 425 ट्रेंच बनाए गए हैं, जिसका आकार 6 फीट लंबाई, 2 फीट चौड़ाई एवं 2 फीट गहराई है। उपरोक्त कार्य योजना में लगभग 40-45 एकड़ जमीन में टीसीबी का कार्य कराया जा चुका है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुसार प्रति एकड़ में 33558 रुपये की लागत से 425 स्टैजर्ड ट्रंच खोदे जा रहे हैं। डुंगरी के नीचले भाग में 12 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा और दो फीट गहरे ट्रंच कम बेड खोदे जायेंगे ताकि डुंगरी के ट्रेंच से निकला अतिरिक्त पानी यहां आकर स्टोर हो जाए। संबंधित योजना के कार्य परिपेक्ष में 125 एकड़ जमीन में पानी लगभग 60 करोड़ 70 लाख 28 हजार 520 लीटर पानी का संचयन होगा। निकटवर्ती गांवों के जमीन में पानी का स्तर बढ़ेगा।

2022 तक डुंगरी से 600 एकड़ क्षेत्र में जल स्तर सुधरेगा

स्ट्रेज्ड ट्रेंच के निकट भूमि क्षरण के रोकथाम हेतु वृक्षारोपण का कार्य का भी प्रबंधन किया जा रहा है। जल संचयन एवं भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रखंड अंतर्गत बहुतायत योजना का संचालन कराया जा रहा है। जमीन का ढलान जहां 8 प्रतिशत तक है वहां ट्रेंच कम बंड एवं जहां 8 से 30 प्रतिशत का ढलान है स्ट्रेज्ड ट्रेंच का निर्माण कराया जा रहा है। प्रखंड अंतर्गत जिन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु तालाब एवं नदी नाला की उपलब्धता नहीं है वहां पर प्रखंड प्रशासन के द्वारा मनरेगा के तहत 28 कुओं का निर्माण कराया गया है। उत्तम कृषि व्यवस्था के लिए सिंचाई हेतु विभिन्न योजनाओं का कार्य कराया जा रहा है।इससे डुंगरी के गोद में बसे गोपालपुर, बारुबेड़ा, गोलकाटा और गेंगड़ा गांव के 600 एकड़ क्षेत्र में जल स्तर सुधरेगा बल्कि खेतों में साल में एक की जगह दो फसल आराम से उगायी जा सकेगी।

किसान प्रभाकर की छह बीघा बेकार जमीन भी बनेगा पानीदार

बारुबेड़ा के युवा किसान प्रभाकर कोड़ा के परिवार की छह बीघा जमीन डुंगरी पर है। उन्होंने बातचीत में कहा, इस जमीन पर न तो कोई पेड़ उगता है और न ही खेती लायक है। इस जमीन से मेरे परिवार को कोई आर्थिक फायदा नहीं है। मुझे खुशी है कि सरकारी खर्च से यहां ट्रेंच बना कर बरसात के पानी को रोकने के साथ सागवान का पौधरोपण किया जा रहा है। इससे जहां हमारे खेतों में सालो भर थोड़ा-थोड़ा पानी रिस कर पहुंचेगा जिससे खेती सुधरेगी वहीं सागवान के पेड़ भविष्य में हमारे लिए मूल्यवान भी साबित होंगे। मैं सरकार की इस योजना से बहुत खुश हूं।

रैयती जमीन के किसानों के लिए सागवान के पौधों का हो रहा पौधरोपण

बारुडीह डुंगरी तीन पंचायतों में फैला है और डुंगरी में रैयती जमीन के अलावा गरु मजरुआ जमीन भी है। रैयती जमीन वाली डुंगरी पर न तो खेती होती है और न ही जंगल उगता है। ऐसे में बकौल प्रखंड विकास पदाधिकारी शंकराचार्य समद, हमने किसानों से बात करके उनको सहमत किया कि बेकार पड़ी जमीन पर सरकार न सिर्फ ट्रेंच अपने खर्च से खोदेगी बल्कि उस पर सागवान एवं अन्य कीमती पौधे लगा कर आपके लिए भविष्य के लिए धन कमाने का मौका भी देगी। ग्रामीणों ने खुशी-खुशी हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

गुमला और तोरपा के पायलट प्रोजेक्ट से मिली प्रेरणा

डुंगरी पर ट्रेंच बना कर नीचले इलाकों के खेतों में वाटर लेवल रिचार्ज करने और डुंगरी पर पौधरोपण कर उसे हरा-भरा करने का पहला प्रयोग गुमला और तोरपा क्षेत्र में किया गया। यहां एनजीओ प्रदान ने पायलट प्रोजेक्ट के जरिए भू-जल रिचार्ज का सफल प्रयोग कर दिखाया तो झारखंड सरकार ने उसे पूरे राज्य के लिए अनुकरणीय मान लिया।

सीसीएल में खुशहाली का आधार, माह का प्रथम शनिवार – सीधा संवाद

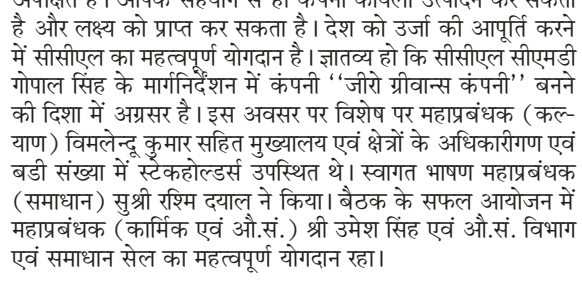

सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह कि अध्यक्षता में ''कायाकल्प समाधान सभा'' का आयोजन किया गया। सीएमडी श्री गोपाल सिंह ने कहा कि ग्रामीण, गरीबों एवं श्रमिकों का सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान सीसीएल प्रबंधन द्वारा दिवंगत कर्मियों के आश्रितों तथा जमीन के बदले कुल 25 अभ्यर्थियो को नियुक्ति पत्र सीएमडी श्री गोपाल सिंह एवं आर.एस. महापात्र एवं महाप्रबंधक द्वारा प्रदान किया गया। इनमें से कुछ स्टेकहोल्डर्स ने पारिवारी समस्या को भी सीसीएल प्रबंधन से अवगत कराया। समस्या का निदान हेतु सीसीएल के सीएमडी श्री गोपाल सिंह ने यह निर्देश दिया है कि सीसीएल परिवार में कुछ नौजवान ऐसे हैं जिन्हें निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण देकर कंपनी उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में मदद करेगी। सीएमडी श्री गोपाल सिंह ने अपने संबोधन में नवनियुक्त अभ्यर्थी को सलाह दिया कि आप कंपनी में ऐसा कार्य करें जिससे लगे कि आप कंपनी के लिए एक संसाधान हैं और उन्होंने सभी को प्रेरित करते हुए कहा कि आप अपने अगले पीढ़ी को गुणवत्ता शिक्षा दें। गोपाल सिंह ने सभी क्षेत्रिय महाप्रबंधक को सलाह दिया कि आप जनसंवाद करें और सकारात्मक रूप से समस्या का निदान करें। निदेशक (कार्मिक) आर.एस. महापात्र ने कहा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान करना प्रबंधन का दायित्व है। सीएमडी की पहल पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है जो सराहनीय है और इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आपके सहयोग से ही कंपनी कोयला उत्पादन कर सकता है और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। देश को उर्जा की आपूर्ति करने में सीसीएल का महत्वपूर्ण योगदान है। ज्ञातव्य हो कि सीसीएल सीएमडी गोपाल सिंह के मार्गनिर्देशन में कंपनी ''जीरो ग्रीवान्स कंपनी'' बनने की दिशा में अग्रसर है। इस अवसर पर विशेष पर महाप्रबंधक (कल्याण) विमलेन्दू कुमार सहित मुख्यालय एवं क्षेत्रों के अधिकारीगण एवं बडी संख्या में स्टेकहोल्डर्स उपस्थित थे। स्वागत भाषण महाप्रबंधक (समाधान) सुश्री रश्मि दयाल ने किया। बैठक के सफल आयोजन में महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औ.सं.) श्री उमेश सिंह एवं औ.सं. विभाग एवं समाधान सेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

फोटो न्यूज

तिवारी बेचर के पास बेचारा पेड़ काट दिया गया

रांची ओवरब्रीज से उतरते ही स्थिति तिवारी बेचर पेट्रोल पंप स्थित पेड़ कट गया

रांची में शहर से बाहर निकलते ही एक अहाते में ये कांस के फूल खिले हुये हें। इनके फूलों को देख कर पहले ये कहा जाता था कि, अब वर्षा ऋतु खत्म हो गयी, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। हाल के कुछ वर्षों में कांस केइन फूलों के खिलने के बाद ज्यादा बारिश हुयी है।

संस्कार देने और भाई बहन के प्रेम का पर्व है कर्मा

कर्मा पूजा झारखंड का प्रचलित लोक पर्व है। यह पर्व हिन्दू पंचांग के भादों मास की एकादशी को झारखण्ड, छत्तीसगढ़, सहित देश विदेश में पुरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास के पश्चात करमवृक्ष का या उसके शाखा को घर के आंगन में रोपित करते है और दूसरे दिन कुल देवी देवता को नवान्न देकर ही उसका उपभोग शुरू होता है। कर्मा नृत्य को नई फ़सल आने की खुशी मेंनाच गा कर मनाया जाता है।

हमारे संस्कृति का प्रतीक है कर्मा।

छत्तीसगढ़ और झारखण्ड के आदिवासी गैर-आदिवासी सभी इसे लोक मांगलिक पर्व मानते हैं। कर्मा पूजा नृत्य, सतपुड़ा और विंध्य की पर्वत श्रेणियों के बीच सुदूर गावों में भी विशेष प्रचलित है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य में 'करमसेनी देवी' का अवतार गोंड के घर में हुआ ऐसा माना गया है। कर्मा की मनौती मानने वाले दिन भर उपवास रख कर अपने सगे-सम्बंधियों व अड़ोस पड़ोसियों को निमंत्रण देत है तथा शाम को कर्मा वृक्ष की पूजा कर टांगी के एक ही वार से कर्मा वृक्ष के डाल को काटा दिया जाता है और उसे ज़मीन पर गिरने नहीं दिया जाता। तदोपरांत उस डाल को अखरा में गाड़कर स्त्री-पुरुष बच्चे रात भर नृत्य करते हुए उत्सव मानते हैं और सुबह पास के किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है।

कर्मा पूजा कथा

कहा जाता है कर्मा धर्मा दो भाई था दोनों बहुत मेहनती व दयावान थे कुछ दिनों बाद कर्मा की शादी हो गयी उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली विचार की थी। वह धरती माँ के ऊपर ही माड़ पसा देती थी जिससे कर्मा को बहुत दुःख हुआ। और नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के जीवन में दुख गये। वहां के लोग कष्ट में रहने लगे। भाई धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गयी और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गयी आस पास कही पानी न था दूर एक नदी दिखाई दिया वहां जाने पर देखा की उसमे पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा की जबसे कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तबसे हमारा कर्म फुट गए है यहाँ का पानी सुख गया है , अगर वे मिले तो उनसे कहा देना। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला उसके सारे फल सड़े हुये थे, उसने भी धर्म से कहा की जब से कर्मा गए है तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते है अगर वे मिले तो उनसे कह दीजियेगा और उनसे उपाय पूछ कर बताईयेगा। धर्म वहां से आगे बढ़ गया आगे उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला उन्होंने बताया की जबसे कर्मा यहांसे गया है उनके सर के बोझ तबतक नहीं उतरते जबतक 3-4 लोग मिलकर न उतारे सो यह बता कर्मा से बता करा कोई उपाय बताना । धर्म वहाँ से भी आगे बढ़ गया आगे उसे एक महिला मिली उसने बताया कि कर्म से पूछ कर बताना की जबसे वो गए हैं खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते है सो इस-के लिए क्या उपाय करें। धर्म आगे चल पड़ा, चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा वहां उसने देखा की कर्मा धुप व गर्मी से परेशान है उसके शरीर पर फोड़े परे हैं और वह ब्याकुल हो रहा है। धर्म से उस-की हालत देखी नहीं गयी और उसने करम से आग्रह किया की वो घर वापस चले, तो कर्मा ने कहा की मैं उस घर कैसे जाऊ जहाँ मेरी पत्नी जमीन पर माड़ फेक देती है तब धर्म ने वचन दिया की आज के बाद कोई भी महिला जमीं पर माड़ नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चले तो उन्हे सबसे पहले वह महिला मिली उससे कर्मा ने कहा की तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था इसी लिए तुम्हारे साथ ऐसा हुवा आगे कभी ऐसा मत करना सब ठीक हो जायेगा। अंत में नदी मिली तो कर्मा ने कहा की तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया आगे तुम्हारे पास कोई आये तो साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सबको उसका कर्म बताते हुये भाई के साथ गांव में प्रवेश किया और पोखर में कर्म का डाल लगा कर पूजा किया उसके बाद घर गया इससे पुरे इलाके में पुनः खुशाली लोट आई और सभी आनंद से रहने लगे। कहते है की उसी को याद कर आज कर्मा पर्व मनाया जाता है ।

एक अन्य कथा के अनुसार

कर्मा पूजा नृत्य के साथ कई लोग इस पूजा की अधिष्ठात्री देवी 'करमसेनी देवी ' को मानते हैं, तो कई लोग विश्वकर्मा भगवान को इसका अराध्य देवता मानते हैं। ज्यादातर लोग इसकी कथा को राजा कर्म से जोड़ते हैं, जिसने विपत्ति- परेशानियों से छुटकारा पाने के उपरांत इस कर्मा पूजा उत्सव नृत्य का आयोजन पहली बार किया था।

आदिवासी लोग कर्मवीर होते हैं जो कृषि कार्य को संपन्न करने के बाद उपयुक्त अवसर पर यह उत्सव मनाते है। इस प्रकार कर्मा पूजा को लेकर और भी कई कहानियां है और ये सभी प्रकृति के प्रति समर्पित है जैसे इस कथा का सार प्रदुषण न फैलाये माना जा सकता है।

आए गेलैं भादो, आंगना में कादो भाई रीझ लागे...

भाई-बहन के प्रेम का पर्व है करम

आए गेलैं भादो, आंगना में कादो भाई रीझ लागे...
झुमइर खेले में आगे बाई रीझ लागे...

भादो का महीना लग गया। आंगन में भादो कर कादो भर गया। ये कादो तो तभी जमेगा, जब आंगन में करम का अंगइन झूमर खेला जायेगा। चारों ओर हरियाली का समंदर लहरा रहा है। गोंदली गोड्डा पक गये हैं। मडुआ गदरा रहा है। नदी-नाले भर गये हैं।अखरा में जोड़ा मांदर बजने लगा है। बहन ससुराल में व्याकुल हो रही है। पिछले साल ही उसका विवाह हुआ है। करम पहुंच गया है। मायके में नवविवाहिता पहुंच कर सखी-सहेलियों, छोटी-बड़ी बहनों और अपनी करम डाइर से मिलने, झूमर खेलने को व्याकुल हो रही है। बहन सोचती है कि कहीं कोइल नदी तो भर नहीं गयी, जिससे भाई न आ पा रहा हो?

एको गो मोर बहिन कोइल पार दिया लोक....

भाई करम के अवसर पर बहन को लाने कैसे न जाये। भरी कोयल नदी पार कर भाई पहुंचता है। बहन के लिए नीले रंग की साड़ी ले जाता है। करम के लिए बहन को उसकी ससुराल से विदा करा लाता है। मायके पहुंचते ही उसकी करम डाइर (सहेली विशेष) सखी सहेली और बहनें जमा हो जाती हैं। करम की योजना बनाती है। भादो का एकादशी शुक्ल पक्ष को करम का त्योहार है। भाई-बहन के स्नेह का त्योहार है। भाई के लिए बहन करम करने आयी है। भाई की सुख समृद्धि के लिए पूजा करने आयी है। सात दिन बच गये हैं। जावा उठाना है। नयी टोकरी, नदी का नया बालू, सात प्रकार के अन्न (धान, गेंहू, जौ, उड़द, मकई, उरद, कुलथी) तैयार है।

गांव भर की बहनें उपवास कर नदी नहाने जाती हैं। नयी टोकरी में नदी का स्वच्छ महीन बालू भर लाती हैं। घर व आंगन को लीप पोत कर उसके मध्य पीढ़ा सजाती है। उस पर बालू भरी टोकरी स्थापित करती हैं। सातों प्रकार के अन्न के दानों को बालू में मिला कर हल्दी पानी से सींचा जाता है। चारों ओर बहनें गोलाकार जुड़ कर जावा जगाने का गीत गाती व नृत्य करती है। जावा मोय जगालो किया किया जावा... सात दिन इसी तरह प्रातः संध्या बहनें मिल कर जावा जगाती हैं। सातों दिन बहनें शुद्ध सादा भोजन करती हैं।

आज एकादशी है। पर्व करने वाली सभी पर्वतीन बहनें जावा देखती हैं। वे सोने से पीले चमकदार उग आये हैं। साग, मांस मछली, तेल, घी सबका जो पूर्ण/ परहेज कर रखी थी। संध्या के समय गांव की सभी बहनें नदी स्नान करने जाती हैं। घर आकर नयी साड़ी और पूर्ण आभूषणों से अपने को सजाती है। गांव के कुछ भाई लोग दिन भर उपवास रख जंगल से करम की तीन डालियां काटने जाते हैं। एक भाई करम की खूबसूरत डाली एक वार से काटता है। नीचे का भाई उसे लोकता है। इसके बाद बड़े आदर सत्कार के साथ उसे घर आंगन लाया जाता है। आंगन में सभी बहनें करम झूर (डाली) के चारों ओर पूजन सामग्री के साथ बैठ गयी हैं। गांव का बूढ़ा पाहन करम की कथा सुनाता जाता है। कथा की समाप्ति के साथ पूजा समाप्त होती है। बहनें फलाहार कर करम झूर के चारों ओर अंगनई झूमर का समां बांध देती हैं। भाई भी मांदर लेकर आ जाता है।

भादो कर एकादशी करम गड़ालों सखी...गीत गूजने लगते हैं।

जावा डलिया को पुष्पहार से अदभुत सजा दिया जाता है। रात भर करम गीत, नृत्य व संगीत से पूरा गांव मधुर संगीत से झूमता रहता है। सुबह होती है। करम राजा, करम गोसाईं, करम देव को अब विदा करना है। उसे द्वार-द्वार ले जाकर नाचती गाती करम देव को विदाई देती हैं।आइझ तो रे करम राजा घरे दुवारे काइल तो रे करम राजा कास नदी तीरे..और करम गोसांई को नदी में जावा डाली के साथ विसर्जित कर दिया जाता है।

गिरधारी राम गौंझू से साभार

विश्व भर में मनुष्य ही अत्याचारी है, श्रीलंका में सौ साल की बूढी हथिनी टिकिरी की मौत जबरन परेड कराने से हो गयी

हाथियों के साथ मनुष्यों की क्रूरता

देवाशीष राय

भले हमारे बच्चे किताबों में इ फोर एलिफेंट पढते हैं, सूंढ वाले इस जीव को कौतूहल से देखते हैं, गणेश के रूप में हम हाथियों की पूजा भी करते हैं, पर धरती पर इन विशालकाय जीवों के प्रति हमने वास्तव में दया कम ही दिखायी है। उल्टे इनका शिकार खाल, दांत और हड्डियों तक के लिये किया गया। हम मनुष्यों ने अपनी बुद्धी से इस बलशाली जीवों पर अत्याचार किये हैं। इनके परिवेश को नष्ट कर इनके रहने का आवास खत्म किया गया और जब ये भूख में भोजन की तालाश में गांवो की ओर रूख किये, तो इन्होंने जान माल को हानि पहुंचानी शुरू कर दी। अब ये वन विभाग से लेकर आम लोगों को सोचना होगा कि , कभी मनुष्यों से दूर जंगलो में रहने वाला हाथी कुछ दशकों से गांवों शहरों में क्यों घुस रहे हैं?

बेड़ो में किसान के लगाये बिजली तार की चपेट में आकर हाथी की मौत

रांची : झारखंड की राजधानी रांची के बेड़ो प्रखंड में एक हाथी की मौत हो गई। इससे गुस्साए लोगों ने एक किसान को जमकर पीटा। मृतक हाथी को देखने के लिए सैकड़ो लोगों की भीड़ भी लग गई थी।

दरअसल प्रखंड के बनटोली जंगल किनारे हड़ीडीपा में एक जंगली हाथी की मौत बिजली करंट लगने से हो गयी। घटना बीते रात की है। बताया जाता है कि ग्रामीणों ने जानबूझ कर खेत में बिजली तार लगाया था, ताकि हाथी मर सके। मृत हाथी को देखने के लिए सैकड़ो लोगो की भीड़ लगी। इसकी सूचना वन विभाग को दी गयी है। इन दिनों क्षेत्र में जंगली हाथी का आतंक बढ़ गया था। इससे ग्रामीण परेशान थे। ऐसे में खेत की ओर हाथी को आने को रोकने और उसे क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने बिजली का करंट बहाल कर दिया गया था। उसमें हाथी के फंसकर टकरा जाने के कारण करंट लगकर मौत हो गई। इससे गुस्साए लोगों ने किसान बुटू की जमकर पिटाई की। इस पूरे वाकये में सबसे दर्दनाक बात ये थी कि बिजली तारों के चपेट में आने के बाद हाथी रात भर चीखता चिल्लाता रहा, उसके झूंड के सभी हाथी वहां बहुत देर तक टिके रहे ताकी वो उसकी जान बचा सकें, अंत में उस हाथी की छटपटा कर मौत हो गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में आये दिन मनुष्यों और हाथियों के बीच टकराव की खबरे आती हैं। और खेतों को नष्ट करने के अलावा घर में रखे अनाज खाने, हड़िया पेय के लालच में मकान तोड़ने और लोगों को कुचल कर मारने की घटनायें आम हैं। ग्रामीणों का क्षुब्ध होना लाजमी है, पर इस बात पर कोई गौर नहीं करता कि आखिर हाथियों ने मानव बस्तियों की ओर रूख क्यों किया है। वन विभाग से लेकर आम लोगों को ये स्वीकार करना होगा कि हमने जंगलों को नष्ट कर इनका प्राकृतिक आवास छिना है। कुछ साल पहले बेड़ों के जंगलों से निकल कर दो हाथी रांची शहर में प्रवेश कर गये थे और पिस्का मोड़ में एक आवासिय परिसर की चा-रदिवारी को तोड़ने कुछ पेड़ों की डालियों वाहनों को तोड़ने के बाद ये वापस जंगलों की ओर चले गये। कुछ पर्यावरणविदों ने बताया कि, ये हाथी जंगलों में भोजन न मिलने और आवास छिन जाने के कारण शहर की ओर आ गये थे। या ये कभी उनके माइग्रेशन का रूट रहा होगा?

श्रींलका में टिकिरी की मौत

श्रीलंका में एक बूढी हथिनी टिकिरी की मौत पिछले दिनों चर्चा में थी। दरअसल टिकिरी बहुत बीमार थी और उसकी उम्र सौ साल के करीब थी, उसे जबरन एक उत्सव में परेड में ले जाया जाता था, कई किमी उस बीमार हथिनी को घुमाया जाता था। उसे कपड़ों से इस तरह से सजा दिया गया था कि उसका बीमार शरीर उसमें ढक जाये, टिकिरी आखिर थक कर गिर गयी और फिर कई दिनों तक उठ न सकी,और अंततः उसने दम तोड़ दिया। बीमार होने पर टिकिरी का इलाज के दरम्यान चादर हटाया गया तब यह दिखा कि उसका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था।

जापान में हाथी दांत की मांग

जापान में हाथी दांत की सबसे ज्यादा खपत होती थी। कुछ पशु अधिकार के लिये काम करने वाले संगठनों ने ये आरोप लगाया कि जापान के कारण अफ्रिका में हाथियों का शिकार हो रहा है। दरअसल जापान में हाल तक ये , मुहर हाथी दांत के उपयोग की परंपरा रही है । वहां का प्रत्येक व्यवसायी हाथी दांत से बना मुहर ही उपयोग करता है। हालांकि शोर होने के बाद जापान में अब इन मुहरों के उपयोग में कमी आयी है।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

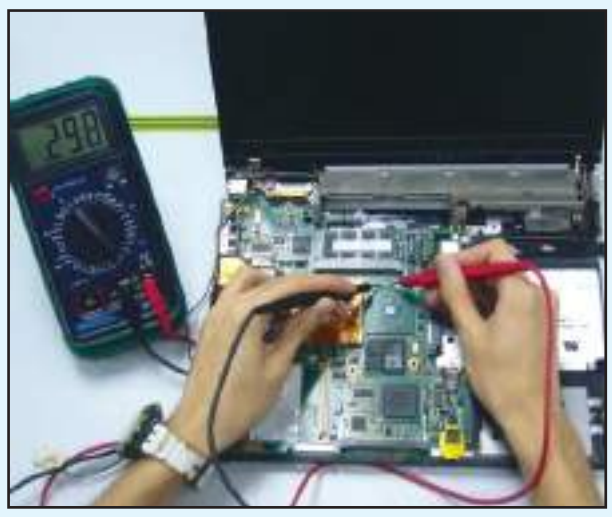

- **Repair your laptop with 3-month warranty**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SunDAY Closed

सन कम्युनिकेशन द्वारा अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2 टीवीएस गली रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित एवं मैसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित। प्रकाशक सह कार्यकारी संपादक : मनोरंजन सिंह, संपादकः मनोज कुमार शर्मा*
आर.एन.आइ. नंबर : JHAHIN00962. email:greenrevolt2019@gmail.com. Ph. 8539978825, 8825374626. इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन ही होंगे।